(**Approved Research Topic** " सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन "

SHORT SYNOPSIS

Submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATION

To

U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

by

SANGITA

Enrollment no. 2200909

Under the supervision of

Dr. Dinesh Singh

Associate Professor

School of Education

School Of Education

U.P. Rajarshi Tandon Open University

Shantipuram, (Sector-F) Phaphamau, Prayagraj- 211021

संगीता

F. No. 405 S.No.: SA 09718339636

School of Education

Certificate

I hereby declare that the short synopsis "---Research Topic · सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन " being submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Education under school of Education of U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj during the academic year-2022-23.

It is a bonafide record of original work carried out under the supervision of Dr. Dinesh Singh and has not been submitted in full or part to any other university or institute for a degree or diploma. Further, it is certified that the short synopsis is plagiarism-free and the repot has been submitted

संगीता
Sangita
2200909

Research Supervisor& Co-Supervisor (If any)

Dr. Dinesh Singh
Associate professor
School of Education
07/05/2025

07.05.2025
Prof. P.K. Astalin
(Director ,School of education)

(Name) Prof. P.K Pandey
(Secretary of DC/ Director, R&D Cell)
07/05/25

F. No. 405, S.No.: SA 0071839636

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध का विषय प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल से संबंधित है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है। विद्यालय शिक्षा की औपचारिक संस्था है। प्रथमिक शिक्षा का बालक के जीवन में विशेष महत्व होता है ।. प्राथमिक शिक्षा का विकास वैदिक युग से आधुनिक युग तक विभिन्न चरणों में हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में अनेकों प्रयास किए गए । इन सबको देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निपुण के अंतर्गत एफ.एल.एन. कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसे प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यापक माहौल तैयार करना है जिसमें बच्चों का समग्र विकास हो सके।

Key tearms

शिक्षा प्राथमिक शिक्षा , बुनियादी साक्षरता , नई शिक्षा नीति 2020 , गणितीय दक्षता , शिक्षा की गुणवत्ता

संगीता

१.१.

CONTENTS

S. NO.	Description	Page no.
1	Introduction	4-7
2	Literature Review	8-10
3	Statement of Problem	11
4	Objectives of the Study	12-13
5	Research Methodology	14-16
6	Expected Outcomes of the Research	16-17
7	References	18

संगीता

सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तावना

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। विद्यालय शिक्षा की औपचारिक संस्था है, जहाँ पर बच्चों को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक विद्यालय एक ऐसी आधारभूत संस्था है जिसका बालक के जीवन में विशेष महत्व होता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। उस समय की शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों में नहीं बटी थी। उस समय की शिक्षा, जनसाधारण को सुलभ नहीं थी बल्कि उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। छठवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का विकास वैदिक धर्म के विरोध में हुआ। जिसमें सभी के लिए शिक्षा के मार्ग खुले थे। इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ जिसमें प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, जहाँ मुस्लिम धर्म से जुड़े संस्कारों के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ ईसाई मिशनरियों के आगमन के साथ आरम्भ हुआ। 1854 में वुड घोषणा पत्र में भी जनसाधारण को व्यवहारिक एवं लाभदायक शिक्षा देने की बात कही गयी। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि की बात भी कही गयी थी लेकिन वुड घोषणा पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इसी क्रम में 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंप देने की बात की। इस रिपोर्ट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण तक पहुँचाने पर जोर दिया गया लेकिन रिपोर्ट द्वारा दिये गये सुझावों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का उचित विस्तार नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के पहले प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किये गये लेकिन वे पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध नहीं हुए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की कि संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए विश्वविद्यालय आयोग

(1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), कोठारी आयोग (1964–66) जैसे प्रमुख आयोगों का गठन किया गया। कोठारी आयोग में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिनमें अंशकालिक शिक्षा व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री, छात्रवृत्ति हेतु उदार नियम आदि के बारे में सुझाव दिये गये। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति अस्तित्व में आयी। इसके अन्तर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता, साक्षरता 10+2+3 संरचना जैसे 17 कार्यक्रमों को शामिल किया गया। किन्तु इस नीति के अधिकांश भाग का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इसके पश्चात् 1986 में नई शिक्षा नीति लायी गयी। जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धन परिवारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, विशेष छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास की सुविधा आदि पर विशेष ध्यान दिया गया । प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई गयी। इन योजनाओं में मुख्य रूप से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन (NEEM), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि। इन सभी प्रयासों के बावजूद आज प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सार्थक सुधार नहीं हो पाया है। इन सबको देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निपुण भारत के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) कार्यक्रम को लाया गया।

निपुण भारत मिशन–2020 –निपुण भारत मिशन–2020 का मुख्य उद्देश्य देश में एक ऐसा व्यापक माहौलतैयार करना है जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके क्योंकि छात्रों के सर्वांगिण विकास पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। युनेस्कों के कुछ विशेषज्ञों के अनुसार माहौल का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और जिससे बालक के चरित्र का निर्माण भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय का वातावरण रूचिपूर्ण और रचनात्मक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि इससे बच्चों के मन में जानने और उद्देश्य–पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। विद्यालयी वातावरण के अन्तर्गत विद्यालय का परिवेश, शिक्षण उपकरण, शिक्षण–कक्ष, फर्नीचर स्वच्छता आदि बातों का समावेश होता है, जिसका गहरा प्रभाव विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर पड़ता है।

एन.ई.पी. 2020 के अन्तर्गत कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष निर्धारित की गई है। इस

संगीता

नीति में वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी छात्रों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुर्नगठित करने की बात की गयी है। यह व्यवस्था 5+3+3+4 क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष की आयु समूह में सुमेलित है। बुनियादी चरण (फाउंडेशनल) पाँच वर्ष में प्रथम 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक तत्पश्चात दो वर्ष कक्षा एक तथा दो के लिए है।इसके बाद प्रारम्भिक चरण (प्रिपेटरी) 3 वर्ष का होगा जिसके अन्तर्गत कक्षा तीन, चार, पाँच की कक्षाएं आयेंगी। प्राम्भिक चरण के पश्चात् मध्यम चरण (मिडिल) 3 वर्ष के लिए है जिसमें कक्षा 6, 7 तथा 8 की कक्षाएं सम्मिलित हैं। 4 वर्ष का माध्यमिक चरण है जिनमें कक्षा 9, 10–11 व 12 की कक्षाएं सम्मलित है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान पर एन.ई.पी. 2020 में विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा प्रणाली ने 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों मेंसार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा जिसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता औरसंख्या–ज्ञान के लिए राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारे 2025 तक प्राप्त किये जा सकने वाले चरणवार कार्यों और लक्ष्यों की पहचान और उसको प्रगति की निगरानी करते हुए अविलम्ब एक क्रियान्वयन योजना तैयारकरेगी।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल बच्चों के सार्वभौमिक विकास की आवश्यकताओं में से एक है जिसके लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सबसे पहले निष्ठा कार्यक्रम (2019) फिर 'मिशन प्रेरणा' 2022 के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर शुरु किया गया । वर्तमान समय में 5 जुलाई 2021 से उ.प्र. सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत इसे क्रियान्वित कराया जा रहा है। इसमें 3 से 9 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2025–26 तक समग्र विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी साक्षरता के अन्तर्गत विद्यार्थियों को बोलने, पढ़ने लिखने और अर्थ समझने में तथा संख्यात्मक कौशल के अन्तर्गत विद्यार्थियों को संख्या विधियों का प्रयोग करके दिन–प्रतिदिन की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाया जाता है। छात्रों द्वारा पढ़ने–लिखने और संख्याओं के बुनियादी संक्रियाएँ करने की क्षमता, आगे की स्कूली शिक्षा

संगीता

और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है लेकिन विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थी हैं जिन्हें बुनियादी साक्षरता तथा संख्याज्ञान नहीं आता है अर्थात् ऐसे बच्चे को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ व घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। इन सब को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्राप्त करने को प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि बुनियादी आवश्यकताओं को (अर्थात् मूलभूत स्तर पर पढना, लिखना और अंकगणित) प्राप्त करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए अन्य नीतियाँ प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों ने 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.) के साथ संबंधित कर उत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षक–शिक्षार्थियों का अनुपात 1 : 30से कम हो और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक–शिक्षार्थियों का अनुपात 1 : 25 से कम होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अलग से ध्यान देने की बात कही है। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में सतत् रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ बच्चों को पढ़ने–लिखने बोलने अंकगणित तथा गणितीय चिन्तन पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर ध्यान देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया कि विगत वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में भाषा एवं गणित की आधारभूत कौशलों में दक्ष नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण वह भाषा व गणित से संबंधित वांछित दक्षता नही प्राप्त कर पा रहे हैं।

संगीता

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

यूनेस्को रिपोर्ट (2005) के अनुसार 'एजुकेशन फॉर ऑल' और अंतराष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन संबंधी आँकड़ों के अनुसार निम्न अथवा कम आय वाले देशों में शिक्षा के निष्पादन स्तर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि इन देशों में विद्यालय में आने वाले सभी बच्चे समान रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, अधिकांश बच्चों में आवश्यक कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा था।

गणित निर्देशिका कक्षा (4–5) बेसिक एवं एडवांस स्तर (2022–23) में उल्लिखित है कि कोविड महामारी के कारण बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ सम्पादित की जी रही है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और 'प्रथम संस्था' द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 एवं 5 के लिए निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत 'बुनियादी साक्षरता' एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन से किया जा रहा है।

द टाइम्स ऑफ इण्डिया – घोष द्वारा लिखित पश्चिम बंगाल में मूलभूत साक्षरता एव संख्यात्मकता में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन सीखने का स्तर अभी भी निम्न बना हुआ है। इसे बेहतर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक मॉडल एकीकृत बाल विकास सेवा केन्द्र 'शिशु अलॉय' लॉन्च किया।

सिमामोरा एट अल. (2019) ने स्थानीय संस्कृति के संदर्भ में निर्देशित खोज सीखने के माध्यम से गणितीय समस्या सुलझाने की क्षमता और आत्म–दक्षता में सुधार पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के नमूने में 200 छात्र को लिया। नमूने को क्रॉयडन, लंदन में यादृच्छिक रूप से चुना गया था। अध्ययन के नतीजे से पता चला कि स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के साथ निर्देशित खोज के माध्यम से सीखना पारंपरिक झुकाव पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी था।

वारिस, जोहान्टो और उटानी (2018) ने गणितीय–समस्या–समाधान क्षमता और आत्मविश्वास के सुधार में समस्या–आधारित शिक्षा की भूमिका का पता लगाया । अध्ययन का नमूने में 66 छात्र थे। गणितीय समस्या समाधान परीक्षण और गणित आत्मविश्वास पैमाने का उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया था। अध्ययन के

संगीता

परिणाम से पता चला कि छात्रों ने पारंपरिक पद्धति की तुलना में समस्या आधारित शिक्षा के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त किए।

मोयेनी, एम (2022) ने ईरानी और इराकी शिक्षकों के गणितीय समस्या समाधान दृष्टिकोण पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन के आँकड़े सर्वेक्षण विधि से एकत्रित किये गये हैं। इस अध्ययन के नमूने में इराक के 16 विद्यालयों के शिक्षक और ईरान के 14 विद्यालयों के शिक्षक शामिल थे। डेटा का विश्लेषण टी टेस्ट के माध्यम से किया गया। अध्ययन के नतीजे में बताया गया कि दोनों देशों के शिक्षकों ने अपनी गणित की कक्षाओं में समस्या–समाधान दृष्टिकोण लागू किया।

अविनोको (2018) ने शिक्षार्थियों की गणितीय समस्या सुलझाने की क्षमता की धारणा में सहकर्मी निर्देश की भूमिका की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया। अध्ययन के नमूने में 300 छात्र शामिल थे। अध्ययन में स्तरीकृत नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम से पता चला कि सहकर्मी निर्देश का उपयोग गणितीय समस्या सुलझाने की क्षमता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था।

वसीर रुखसाना, जॉन० तस्लीमा (2016) द्वारा किये गये अध्ययनों में पाया गया कि जीवन के शुरुआती आठ साल बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि होती है। अनुसंधान में इन्होने पाया कि दुनियाभर में शिक्षा प्रणालियाँ विभिन्न तरीकों से लड़खड़ा रही है। छात्रों के मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल उन कौशलों का एक समूह है जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहा है। एन.ई.पी.– 2020 मे दृढ़ता से वकालत की गई है और 2026 तक कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए निपुण भारत का संचालन किया गया है।

कुमार इंदल (2014), ने अपने अध्ययन में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मूलभूत स्तम्भ माना है। उन्होंने भारत में बच्चों के मूलभूत साक्षरता कौशल की स्थिति और उनके सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और स्कूल स्तर की विशेषताओं के संदर्भ में इसके निर्धारकों का विश्लेषण किया है और परिणाम में पाया कि परिवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्कूल की पसंद, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने में

संगीता

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एन.ई.पी. (2020)एफ.एल.एन के माध्यम से छात्रों में सीखने के परिणामों की प्रगति के लिए प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता हासिल करने के उद्देश्य को 2025–26 तक पूरा करने हेतु रखा गया है।

सिकदार (2007) बड़ौदा शहर के प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता संबंधी अध्ययन के परिणामों में पायें कि जिस विद्यालय की संरचना तथा संसाधन ठीक थे उनके छात्रों की उपलब्धि अच्छी थी तथा जिन विद्यालयों के पास उचित संसाधन की कमी थी उनके उपलब्धि स्तर में भी गिरावट पायी गई।

समीर (2012) ने बांग्लादेश में प्राथमिक स्तर के अधिगम उपलब्धि पर पूर्व विद्यालयी शिक्षा के प्रभाव संबंधी अध्ययन में पाया कि पढ़े–लिखे परिवार के बच्चे ही पूर्व विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करते थे । यद्यपि पूर्व विद्यालयी स्तर बच्चों की उपस्थिति, प्राथमिक अधिगम उपलब्धि की भविष्यवाणी तो नहीं करता लेकिन आर्थिक–सामाजिक विद्यालय माहौल, सहयोग आदि से अधिगम प्रभावित होती है।

अध्ययन की आवश्यकता

छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने तथा महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए बुनियादी साक्षरता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल स्कूल में आगे की अकादमिक उपलब्धि के लिए और जीवनपर्यन्त सीखते रहने के लिए आधार प्रदान करते हैं। साक्षरता, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता और धार्मिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो शिक्षा संपत्ति, रोजगार और नागरिक भागीदारी तथा आपसी सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इन्हीं आवश्यकताओं की कमियों को दूर करने के लिए सम्बंधित अनुसंधान अति आवश्यक है।

अनुसंधान की प्रासंगिकता

भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर संचालित किया है। इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कौशल भी आता है। इसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को समझ के

संगीता

साथ पढ़ना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना तथा दैनिक जीवन की मूलभूत संक्रियाओं को सीखाना है। शोधार्थी द्वारा **"सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन"** को शोध के रूप में लिया गया है जिसमें शोधार्थी अध्ययन के फलस्वरुप यह देखना चाहता है कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान–कौशल के क्रियान्वयन के पश्चात् विद्यार्थी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल के लक्षण को प्राप्त कर पायें हैं या नहीं?

पूर्व अध्ययनों में अध्ययनों में यह पाया गया है कि बुनियादी साक्षरता बच्चों को पढ़ने, लिखने, बोलने और विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि के मूल अवधारणाओं को समझने और उनके बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अपने आस–पास की दुनिया के बारे में जागरूक और सचेत बनाता है तथा उन्हें अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों की भूमिका समझने और निभाने में सक्षम बनाता है, इसलिए प्रस्तुत शोध का विषय का चयन कियागया है। पूर्व अध्ययन में यह पाया गया है कि संख्यात्मक कौशल का अध्ययन बच्चों को गणित के मूल अवधारणाआ और अनुप्रयोगों को सिखाने में मदद करता है। संख्यात्मक कौशल का अध्ययन बच्चों में कारक विश्लेषण और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करती है और विद्यार्थियों को अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने तथा उसमें भाग लेने के लिए आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान बढ़ता है इसलिए प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया गया है।

अनुसंधान प्रश्न–

1– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता का स्तर क्या है?

2– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संख्यात्मक कौशल का स्तर क्या है?

समस्या कथन

"सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक

संगीता

कौशल का तुलनात्मक अध्ययन"

संक्रियात्मक परिभाषा–

प्राथमिक विद्यालय –प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव में प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा से लिया गया है।

बुनियादी साक्षरता –प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव में बुनिंयादी साक्षरता से तात्पर्य विद्यार्थियों के बोलने, पढ़ने, लिखने तथा अर्थ समझने की योग्यता से लिया गया है।

संख्यात्मक कौशल – प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्ताव में संख्यात्मक कौशल से तात्पर्य विद्यार्थियों को संख्याविधियों का प्रयोग करके दिन–प्रतिदिन की गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता से लिया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

6– सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के संख्यात्मंक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

7– निजी प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

8– निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

संगीता

9- शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

10- शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

11- शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

12- शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

13- शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

14- शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुनियादी साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

15- शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

16- शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अनुसंधान परिकल्पनाएं

1- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

2- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

3- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

4- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

5- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

6- सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

7- निजी प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के बुनियादी साक्षरता में

संगीता

: SA 0071839636

सार्थक अंतर है।

8– निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं के संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

9– शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

10– शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

11– शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

12– शहरी तथा ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

13– शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

14– शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की बुनियादी साक्षरता में सार्थक अंतर है।

15– शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

16– शहरी तथा ग्रामीण निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्यात्मक कौशल में सार्थक अंतर है।

अनुसंधान अभिकल्प

अनुसंधान विधि – अनुसंधान की प्रणाली द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, अनुसंधानकर्त्री द्वारा विवरणात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा ।

जनसंख्या – प्रस्तुत अनुसंधान के लिए वाराणसी जनपद के सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। अध्ययन हेतु प्रस्तावित वाराणसी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों की जनसंख्या निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित है –

सारिणी संख्या –1 वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों की जनसंख्या

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय		शहरी प्राथमिक विद्यालय	
सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
791	513	178	402

न्यादर्श एवं न्यादर्शन विधि –प्रस्तुत शोध कार्य में प्रतिदर्श के चयन हेतु शोध्कत्री द्वारा

संगीता

0071839636

सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी कार्यालय से वाराणसी जनपद में संचालित प्राथमिक विद्यालयों की सूची प्राप्त की जाएगी तत्पश्चात प्राप्त सूची को शोधकत्री द्वारा शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों के आधार पर विद्यालयों को व्यवस्थित किया जायेगा । शोधकर्ती द्वारा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों से 10 सरकारी एवं 10 निजी तथा शहरी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों से 10 सरकारी एवं 10 निजी विद्यालयों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित प्राथमिक विद्यालयों से 20 विद्यार्थियों (10 छात्र एवं 10 छात्रा) का चयन शोधकर्ती द्वारा स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि से किया जाएगा। जिसमें सिर्फ कक्षा चार के विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रस्तावित प्रतिदर्श का विवरण निम्नवत होगा –

सारिणी संख्या –2 वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालयों तथा विद्यार्थियों का न्यादर्श

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय				शहरी प्राथमिक विद्यालय			
सरकारी विद्यालय (10)		निजी विद्यालय (10)		सरकारी विद्यालय (10)		निजी विद्यालय (10)	
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
100	100	100	100	100	100	100	100
200		200		200		200	

शोध उपकरण– प्रस्तुत अनुसंधान में आँकड़ो के एकत्रीकरण के लिए स्वनिर्मित उपकरण (प्रश्नावली) का प्रयोग किया जाएगा जिसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत प्रचलित भाषा एवं गणित निर्देशिकाओं (कक्षा 5 – 4बेसिक एवं एडवांस स्तर) के एफएलएन कार्यक्रम को आधार बनाया जाएगा।

सांख्यिकी विधियाँ – प्रस्तुत अनुसंधान में आँकड़ों प्रकृति के आधार पर उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाएगा।

सीमांकन – प्रस्तुत अनुसंधान हेतु केवल वाराणसी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को शामिल

संगीता

जाएगा। प्रस्तुत अनुसंधान के लिए प्राथमिक स्तर के केवल सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा।

शोध के अपेक्षित परिणाम

यह शोध "सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का तुलनात्मक अध्ययन" पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच साक्षरता (जैसे पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता) और संख्यात्मक कौशल (जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग) में क्या अंतर है, विशेष रूप से जब वे विभिन्न प्रकार के विद्यालयों – सरकारी बनाम निजी – में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। इस शोध के अपेक्षित निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

• **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में अंतर का स्पष्ट मूल्यांकनः**

शोध से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता (जैसे कि कहानी पढ़ना, वाक्य बनाना) और संख्यात्मक कौशल (जैसे अंकगणितीय संचालन) में मौजूदा अंतर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। यह अंतर स्कूल की शैक्षिक गुणवत्ता, संसाधनों, शिक्षकों की योग्यता, और शिक्षण विधियों के कारण हो सकता है।

• **शैक्षिक असमानता की पहचानः**

इस अध्ययन से यह भी समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार शैक्षिक असमानता का प्रभाव बच्चों के सीखने की नींव पर पड़ता है। यदि निजी विद्यालयों के छात्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन–से कारक उत्तरदायी हैं – जैसे कि अभिभावकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, विद्यालय की अवसंरचना, कक्षा का आकार, या व्यक्तिगत ध्यान।

• **नीति निर्माण में योगदानः**

शोध के निष्कर्ष शिक्षा नीति–निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे यह जानकारी मिल सकती है कि किन क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों को सुधार की आवश्यकता है

संगीता

और किन नीतियों को अपनाकर सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को निजी विद्यालयों के समकक्ष लाया जा सकता है।

- **शिक्षकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार की संभावना:**

यदि अध्ययन से यह पता चलता है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन में कमी का कारण शिक्षण विधि या प्रशिक्षण की कमी है, तो इससे शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता को उजागर किया जा सकता है।

- **सामाजिक जागरूकता में वृद्धि :**

यह शोध अभिभावकों, समुदायों और सामाजिक संगठनों को भी यह समझने में मदद करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल विद्यालय के चयन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छात्रों को मिलने वाले शैक्षणिक वातावरण, घर में समर्थन, और शिक्षकों की भूमिका पर भी आधारित होती है।

- **भविष्य के अनुसंधान के लिए आधार:**

यह अध्ययन आने वाले समय में अन्य शोधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा, विशेष रूप से ग्रामीण बनाम शहरी विद्यालयों, सह–शिक्षा बनाम बालक/बालिका विद्यालयों, या डिजिटल बनाम पारंपरिक शिक्षा पद्धति की तुलना करने वाले अध्ययनों के लिए।

इस प्रकार, यह शोध न केवल शैक्षिक अंतर को उजागर करेगा, बल्कि उन ठोस उपायों की ओर भी इशारा करेगा, जिनसे प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है।

*****

संगीता

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- कुमार, पी. (2016) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ गुणवत्ता के संदर्भ में भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 37 अंक 2 अक्टूबर, 2016
- इवांस, डी.के., और हैरिस, एस. (2021). क्या सरकारों और दानदाताओं को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए? वैश्विक विकास केंद्र, 1–23
- घोष, एल. (2021)। पश्चिम बंगाल में मूलभूत साक्षरता औरसंख्यात्मकता, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 12–14
- लिस्टर, जे. (2013). वयस्कों पर ख़राब संख्यात्मक कौशल का प्रभावः अनुसंधान समीक्षा, राष्ट्रीय वयस्क साक्षरता और संख्यात्मकता अनुसंधान एवं विकास केंद्र (एनआरडीसी)।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मुरलीधरन, आर., और कौल, वी. (1999). एकीकृत प्रारंभिक बचपन विकासः भारतीय अनुभव। शिक्षाः अंतर–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य (पृष्ठ 287), रूटलेज ।
- प्रिया, जे. जे. और कलैयारासी, एन. (2015)। ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों की गणितीय समस्या सुलझाने की क्षमता और अमूर्त तर्क । श्री सारदा जर्नल ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज ।
- पटनायक, एम.एस. (2000) समस्याओं को हल करना सीखना और समस्या समाधान के रूप में सीखना शिक्षा विश्वकोश खंड। ली. इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली ।
- शाइनहोल्ट्स और मिसेल, जे. (2009)। मध्यम विद्वानों के बीच रचनात्मक समस्या समाधान में उत्पादक और मूल्यांकन सोच पर सकारात्मक मनोदशा का प्रभाव। निबंध सार अंतरराष्ट्रीय ।
- पिल्लई, कमला एस. (1985)। गणित की उपलब्धि के संबंध में समस्या समाधान के प्रति दृष्टिकोण: शिक्षा में प्रयोग ।

*****

संगीता

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language Hindi

Submission Information

Author Name	Sangita
Title	सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यातयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कोशत का तुलनात्मक अध्ययन
Paper/Submission ID	3587549
Submitted by	rjmauryaupri@gmail.com
Submission Date	2025-05-07 11:46:03
Document type	Synopsis

Result Information

Similarity **2%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

07/05/2025
(Dr. Dinesh Singh)

संगीता
07/05/2025

DrillBit

DrillBit Similarity Report

2	2	A	A-Satisfactory (0-10%)
SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE	B-Upgrade (11-40%)
			C-Poor (41-60%)
			D-Unacceptable (61-100%)

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	Paper Submitted to Awadesh Pratap Singh University, Rewa	2	Student Paper
2	Paper Submitted to Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya	<1	Student Paper

07/05/2025
(Dr. Dinesh Singh)

संगीता
07/05/2025